

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 65-2016/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, APRIL 29, 2016 (VAISAKHA 9, 1938 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 अप्रैल, 2016

संख्या 20/25/2011—6 क 1.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम 24) की धारा 2 के खण्ड (24) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए सोहना नगरपरिषद के उक्त खण्ड को अनुसूची में यथा—विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अनिर्मित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करते हैं, अर्थात:—

अनुसूची

गांव	जिला	खसरा संख्या	कुल क्षेत्र
सोहना	गुड़गांव	228 / / 22 (8-0)	20 कनाल 4 मरला (2.52 एकड़)
		23 / 2 (3-14), 24(8-0)	
		और 26 (0—10)	

अनिल कुमार, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

Price: Rs. 5-00 (4419)

HARYANA GOVERNMENT

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 29th April, 2016

No. 20/25/11-6C1.— In exercise of the powers conferred by clause (24) of Section 2 of the Haryana Municipal Act, 1973 (Act 24 of 1973), the Governor of Haryana, hereby, notifies the area as specified in the schedule given below falling within the limits of Municipal Council, Sohna, as "un-built" area for the purpose of the said clause namely:-

SCHEDULE

Village	District	Khasra Nos.	Total Area
Sohna	Gurgaon	228//22 (8-0), 23/2 (3-14), 24 (8-0) and 26 (0-10)	20 Kanal 4 Marla (2.52 acres)

ANIL KUMAR, Principal Secretary to Government Haryana,

Urban Local Bodies Department.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 अप्रैल, 2016

संख्या 14/एस0टी0-1/ह030 6/2003/धा0 59/2016.— चूंकि, राज्य सरकार की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में तूरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है ;

अब, इसलिए, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) की धारा 59 की उप–धारा (1) के परन्तुक के साथ पिठत उक्त उप–धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क, ख तथा ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,

- 1. अनुसूची क में,-
 - (i) क्रम संख्या 13 तथा उसके सामने प्रविष्टि का लोप कर दिया जाएगा।
 - (ii) खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 13 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके साने प्रविष्टियां जोड दी जाएंगी, अर्थात:—
 - "14 सूती धागा, जब राज्य में स्थापित विनिर्मित इकाई द्वारा निर्मित करके बेचा जाता है, 0%"। किन्तु रुई की छीजन से निर्मित सूती धागा तथा सूती धागे की छीजन शामिल नहीं हैं।
- 2. अनुसूची ख में,-
 - (i) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—
 - "4क बेसन बिनौला तथा ऑयल केक (खल)";
 - (ii) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 12 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—
 - "12क छोटा (मिनी) टोका (रसोई के लिए पत्तेदार सब्जियों का कर्तक)";

- (iii) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 44 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
 - "44 सभी प्रकार के जूते (चमड़े से बने जूतों को छोड़कर किन्तु इसमें हवाई चप्पलें और उनकी पिट्टयां शामिल हैं) जिनकी अधिकतम खुदरा कीमत ₹500 / — प्रति जोड़ी से अधिक नहीं है, परन्तु अधिकतम खुदरा कीमत जूते पर अमिट रूप से चिहिनत या उभरी हुई है तथा जूते के 'अपर'।"।
- 3. अनुसूची ग में,-
 - (i) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 4 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:—
 - "4 सभी प्रकार के धागे जिसमें सिलाई धागा तथा सभी प्रकार के धागों की छीजन शामिल है, किन्तु सूती धागा जब राज्य में स्थापित विनिर्मित इकाई द्वारा निर्मित करके बेचा जाता है. शामिल नहीं है":
 - (ii) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 29 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

"29क बैटरी संचालित इलैक्ट्रिकल वाहन";

(iii) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 94 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

"९४क वॅ:मिसेल (सेवई)";

- (iv) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 98 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
 - "98 मैदा तथा सूजी सहित गेहूँ का आटा, चावल का आटा, चने का आटा, जौ घाट, जौ का आटा तथा सत्तू, गेहूँ या जौ का दलिया, क्षतिग्रस्त गेहूँ, राजमा, लोबिया, रौंगी सेगो (साबूदाना), सोयाबीन मील तथा सोयाबीन का आटा"।
- (v) खाना 1 तथा 2 के नीचे, क्रम संख्या 100ड. तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:—

"100च सभी प्रकार के जूते सिवाय उनके जो अनुसूची ख की प्रविष्टि 44 के अन्तर्गत आते हैं;"।

रोशन लाल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th April, 2016

No. 14/ST-1/H.A.6/2003/S.59/2016.— Whereas, the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 59 read with proviso to said Sub-section of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedules A, B and C appended to the said Act with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),-

- 1. in Schedule A,-
 - (i) serial number 13 and entry thereagainst shall be omitted.

- (ii) under columns 1, 2 and 3, after serial number 13 and entries thereagainst, the following serial number and entires thereagainst shall be added, namely:-
 - "14 Cotton yarn, when manufactured and sold by the manufacturing unit established in the State, but not including the cotton yarn waste and yarn manufactured from cotton waste.

0%".

2. in Schedule B.–

- (i) under columns 1 and 2, after serial number 4 and entry thereagainst, the following serial number and entires thereagainst shall be inserted, namely:-
 - "4A Besan, Binola and Oil Cake (Khal)";
- (ii) under columns 1 and 2, after serial number 12 and entry thereagainst, the following serial number and entires thereagainst shall be inserted, namely:-
 - "12A Chhota (Mini) Toka (leafy vegetables cutter for Kitchen)";
- (iii) under columns 1 and 2, for serial number 44 and entry thereagainst, the following serial number and entires thereagainst shall be substituted, namely:-
- (iv)
- "44 All kinds of footwear (excluding Footwear made of leather but including Hawaii chappals and straps thereof) with maximum retail price not exceeding `500 per pair provided that the maximum retail price is indelibly marked or embossed on the footwear itself, and shoe-uppers".

3. in Schedule C,-

- (i) under columns 1 and 2, for serial number 4 and entry thereagainst, the following serial number and entires thereagainst shall be substituted, namely:
 - all types of yarns including sewing thread and wastes of all types of yarns but not including cotton yarn when manufactured and sold by the manufacturing unit established in the State";
- (ii) under columns 1 and 2, after serial number 29 and entry thereagainst, the following serial number and entires thereagainst shall be inserted, namely:-
 - "29A Battery operated electrical vehicle";
- (iii) under columns 1 and 2, after serial number 94 and entry thereagainst, the following serial number and entires thereagainst shall be inserted, namely:-
 - "94A Vermicelli (Sewian)";
- (iv) under columns 1 and 2, for serial number 98 and entry thereagainst, the following serial number and entires thereagainst shall be substituted, namely:-
 - "98 Wheat atta including maida and sooji, rice flour, gram flour, barely ghat, barely flour and sattu, dalia of wheat or barely, damaged wheat, rajmah, lobia, rongi, sago (sabudana), soyabean meal, and soyabean flour";
- (v) under columns 1 and 2, after serial number 100E and entry thereagainst, the following serial number and entires thereagainst shall be inserted, namely:-
 - "100F All types of footwear except those covered by entry 44 of Schedule B;".

ROSHAN LAL,

Additional Chief Secretary to Government Haryana, Excise and Taxation Department.

HARYANA GOVERNMENT

MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT SECTOR-17, CHANDIGARH

e-Auction Notice

The 29th April, 2016

No. DMG/HY/e-Auction/Gypsum/HSR/Bhi/2016/2241.—

It is hereby notified for the information of General Public that mining lease for extraction of **Gypsum**, a minor mineral from mines in village **Saharwa** of the districts of Hisar and villages **Dariyapur & Garanpur Kalan** of Bhiwani will be granted "whole as one unit" through the process of e-Auction. It is informed to all concerned persons/parties that who are otherwise not specifically debarred or are not defaulter on account of government dues as per condition No. 6 of this notice *can participate in the e-Auction*. The e-Auction will be held on 2nd and 3rd June, 2016 and bids can be submitted from 02.06.2016 at 09:00 AM to 03.06.2016 till 12.00 noon, extendable maximum up to 04:00 PM. The important instructions for participation in the online e-Auction are as under:

- A. The bids shall be made online on the **e-procurement** website https://haryanaeprocurement.gov.in.
- B. The intending bidders before participation in the e-auction/ bidding process will be required to create **their** <u>user account online</u> by selection the option of e-auction from discipline column and obtain <u>user-id/password</u> on the website https://haryanaeprocurement.gov.in (If already created user account, this step needs to be skipped). For necessary instructions regarding participation in e-Auction of mines, please visit the aforementioned website and click on the available link "How to..." at the Home Page.
- C. After getting the *user account created*, the prospective/ intending bidders shall **upload** following **documents** (in PDF format not exceeding limit of 10 MB for individual document) along with deposition of earnest money (EMD) and e-service fee in order to participate in the e-Auction by 30th May, 2016 upto 05:00 PM anytime after the publication of this document:
 - (i) "No Dues Certificate" from the authorised officer or an affidavit sworn before any Magistrate to the effect that no amount of lease money, royalty, dead rent or surface rent is due in respect of any mining lease/mining lease or mineral concession held by him earlier or in respect of any mineral concession currently held by him or his family members;
 - (ii) Copy of the **Partnership deed or Article of Association (in case of company),** or an affidavit (in case of sole proprietor); No transfer or addition or deletion of the partners/Directors will be permissible before execution of the agreement;
 - (iii) A copy of **authority letter** by the Partnership Firms or **Copy of resolution** of the Board of Directors (BoD) of the Company in favour of the person who shall be offering the bids online for such intending agency;
 - (iv) **Earnest Money** equal to 10% of the reserve price of the mining lease area for which bid has to be made, rounded by an amount of Rs.10,000/-, through online payment in due course of time i.e. up to 30.05.2016 till 05:00 PM. In case the intended bidder fails to pay online EMD fee under the stipulated time frame will not be allowed to enter in e-Auction of mine(s). The payment for EMD fee can be made by eligible bidders online through RTGS / NEFT or OTC. (Please refer to important Payment Guidelines under Annexure 'A' provided by online payment gateway service provider i.e. ICICI Bank).

The payment shall be made against the beneficiary account number as mentioned in the challan to be generated online at the **e-Procurement portal https://haryanaeprocurement.gov.in**.

- (v) Details of the bidding agency in case of requirement of **refund of EMD** (a) Refund Account Name (b) Refund Account No. (c) IFSC code of the Bank. Note: Please cross check the information to be submitted online before saving the same as the information in non editable.
- (vi) The Bidders shall have to pay **e-Service Fee of Rs.1000/- online** by using the service of secure electronic payment gateway. The secure electronic payments gateway is an online interface between bidders and online payment authorization networks. The Payment for **e-Service Fee** can be made by eligible bidders online directly through **Debit Cards & Internet Banking Accounts**.
- **Note:** Any document uploaded as per (i), (ii) and (iii) above at later stage/after auction found to be wrong/false shall invite revocation/cancellation of bid and forfeiture of amount deposited at the

time of auction apart from debarring the bidder from participation in any subsequent bids for a period of 5 years.

D. In case of any query regarding process of **e-Auction**, the intended bidder can contact the service provider at below mentioned address:

M/s Nextenders (India) Pvt. Ltd. O/o Director Supplies and Disposal Haryana, SCO – 09, IInd Floor, Sector – 16, Panchkula – 134108 E - mail: Chandigarh@nextenders.com Help Desk: +-91-172-2582008-09. 2618292 and 1800-180-2097 (Toll Free Number)

Note- A training-cum-orientation programme for the intending bidders will be held on **14th**, **21st** and **28th May**, **2016** at Chandigarh office of *M/s Nextenders* (*India*) *Pvt. Ltd.* from 11:00 AM to 12:00 Noon. Parties interested in attending the same are requested to contact/confirm participation to Sh. Kanwarjeet Singh Mobile 09592259876, Sh. Sat Dev Sharma 9872252144 or the helpdesk on Toll Free No. 1800-180-2097 and 0172-2582008/2582009/2618292 or through E-mail: chandigarh@nextenders.com.

- E. Any bidder interested to participate in the auction can submit his bid/s from **02.06.2016 from 09:00 AM to 03.06.2016 till 12:00 noon**.
- F. However, in case any bid in respect of any mine/ block is received 10 minutes prior to time fixed for closure for the bids i.e. bid received between 11:50 AM to 12:00 Noon then the time for closure of the auction would be extended automatically by 10 minutes, so that equal opportunity is made available to the persons participating in the bidding process. Such extensions of ten minutes will continue till bids are received within next 10 minutes of last bid for any of the mine, otherwise the same would get concluded.
- G. In case the bidding would continue during such extensions of 10-10 minutes, the bidding process will finally conclude at 04:00 pm and no further extension would be given thereafter.
- H. The minimum bid incremental value during the initial time provided i.e. on **03.06.2016** upto 12:00 noon will be in multiple of Rs. 50,000 (Fifty thousand). However the increment during extended period i.e. **03.06.2016** from 12:00 noon till 04:00 PM will be multiple of 100000 (one lakh) instead of 50,000 (Fifty Thousand).

The details of the areas for grant of mining lease along with reserve price and period of mining lease which are to be granted on leases and other terms and conditions of the auction are given below:

Sr. No.	Name of village	Khasra No. of mining lease area (sub area)	Tentative village- wise area (in hectare)	Total tentative Area (in Hectare)	Reserve Price (Rs. in lacs) per annum	Period of lease (in year)
1.	Saharwa (District Hisar)	143/12m,13m, 17m, 18, 19m, 22m, 23m, 24m, 25m. 146/3m, 4, 5m, 6m, 7, 8m, 12m, 13m, 14, 15m, 16m, 17m, 18m, 24m, 25m. 180/1m, 9m, 10m, 11m, 12m, 13m, 18m, 19m. 181/5m, 6m.	8.30	10.20	40.00	10
2.	Dariyapur (District Bhiwani)	590/444 (0.40) 269/1 (0.50)	0.90			

Sr. No.	Name of village	Khasra No. of mining lease area (sub area)	Tentative village- wise area (in hectare)	Total tentative Area (in Hectare)	Reserve Price (Rs. in lacs) per annum	Period of lease (in year)
3.	Garanpur Kalan (District Bhiwani)	62/22m, 23m, 24m. 80/2m, 3m, 4m.	1.00			

The terms and conditions of the Auction:

- 1. The period of lease shall commence w.e.f. the date of grant of environmental clearance by competent authority as required under EIA notification dated 14.09.2006 and as amended from time to time by the MoEF, GoI or on expiry of a period of 12 months from the date of acceptance of highest bid/issuance of "Letter of Intent", (LoI) whichever is earlier;
- 2. Any site/lease area can be withdrawn from the Auction without assigning any reason;
- 3. Due care had been taken in specifying the details of the areas of the mining lease. However, in case of any inadvertent clerical mistake, the same shall be got rectified/corrected even after the auction but before execution of lease deed:
- 4. The lease areas are **Tentative** and are being notified on 'as is where is basis' and all prospective bidders are expected and presumed to have surveyed the areas to make their own assessment for the potential of the areas for which bids are to be offered. The State Government shall not be responsible for any kind of loss in land / area or any other loss to the bidders/lessees at any point of time (before or after grant of lease) on account of reduction of land/ area or otherwise. Further, the bidders are also expected to have gone through the terms and conditions of auction notice and also the applicable Acts and Rules for undertaking mining;
- 5. No request regarding reduction in bid amount on account of reduction in land/area of the Mining lease, on any account including that of change in description of khasra numbers / location etc. at any stage will be entertained on any ground. This shall also include any loss/reduction of area for actual mining for want of compliance of applicable laws/restrictions for mining or part of the leased area had already been operated in the past. Needless to state that this also includes the changes, if any, as per condition No. (3) and the prospective bidder shall give their bids taking account of all such eventualities;
- 6. No person shall be eligible to participate in the Auction, who or any of his family members is a defaulter of any mining dues in respect of any mineral concession granted in the past or any other current mineral concession. In case any of the partners of a Partnership Firm or a Director of a company participating in the auction process or any of their family members are found to be defaulter, the bidder firm/company would be held ineligible;

Further, any person firm or company as the case may be who had been specifically debarred to participate in the auction would not be eligible to participate in the auction.

- 7. In case any bidder participated in the auction is found to be in arrears at any stage, his bid shall be revoked / cancelled with forfeiture of the amount deposited by him;
- 8. All intended participant can view the highest quoted bid during online bidding process. The highest bidder will be informed for confirmation of the same through **e-mail** and **SMS alert** at his online registered email and Mobile Number respectively;
- 9. The highest bid received shall become the 'annual dead rent' amount payable by the bidder/lessee. The amount of annual dead rent initially determined on the basis of competitive bids/auctions shall be increased by 25% on completion of each block of three years;

Explanation: If the initially determined annually bid/lease Rs. 100/, it shall be increased to Rs. 125/with the commencement of the fourth year and to Rs. 156.25 with the commencement of the 7th year and so on and so forth for the next each block of three years.

- 10. The highest bidder would be informed about the same- confirmation that he being declared as **highest bidder** as per which he shall be liable to deposit 25% of the annual bid/dead rent as "security" and one month's advance dead rent. The above said amount shall be deposited as per following schedule:
 - (a) an amount equal to 10% of the annual dead rent/ highest bid, after adjusting the EMD deposited for said mine, as 'initial bid security' within 24 hours of conclusion of the bidding process. The payment has to be made through RTGS/NEFT by secured online payment gateway;
 - (b) balance amount of bid security i.e. 15% of the annual dead rent along with one month's advance dead rent before commencement of the mining operation or before expiry of the period of 12 months, whichever is earlier:
- 11. In case the highest bidder fails to deposit 10% of the annual dead rent/bid amount online towards the "Initial bid Security" within 24 hours given for the same the earnest money deposited shall stand forfeited. Further such bidder(s) shall not be eligible to participate in any future auctions/Tenders/competitive bidding process in respect of any area for obtaining mineral concession in the State for a period of 5 years;
- 12. **The bids offered/ received during the e-auction process shall be** provisionally accepted and the Director shall obtain the orders of Government thereon. No bid shall be regarded as successful bid unless accepted by the Government
- 13. After deposit of 10% of the bid amount (as initial bid security) after the conclusion of auction by the highest bidder(s), No request from the highest bidder(s) regarding revocation or the withdrawal of the highest bid shall be considered. In case, any such request is made, the same shall be followed by the Penal action i.e. 10% amount deposited towards initial bid security shall stand forfeited and un-paid 15% amount towards security shall be recovered as arrears of land revenue and such bidder(s) shall debarred from participation in any future auctions/Tenders/competitive bidding process in respect of any area for obtaining mineral concession in the State for a period of 5 years;
- 14. The earnest money deposited by the bidders other than highest bidders shall be refunded upon completion of the auction proceedings;
- 15. After the acceptance of highest bid by the State Government and on issuance of Letter of Intent, the LoI holder shall execute a lease deed in Form ML-I appended to the 'Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012' within a period of 90 days of the order of grant of LoI;
- In case of failure to execute the lease deed, after issuance of acceptance of bid/LoI within prescribed period, the acceptance/LoI shall be deemed to have been revoked and 10% amount deposited towards initial bid security shall stand forfeited and un- paid 15% amount towards security shall be recovered as arrears of land revenue and such bidder shall debarred from participation in any future auctions/Tenders/competitive bidding process in respect of any area for obtaining mineral concession in the State for a period of 5 years;
- 17. After execution of lease deed, either before commencement of the mining operation or before expiry of the period of 12 months from the date of issuance of LoI, whichever is earlier, in case of failure to deposit the balance 15% amount towards security (as required under clause 10(b) above) the acceptance of bid/issuance of LoI/execution of lease deed shall be deemed to have been revoked and 10% amount deposited towards as initial bid security after the conclusion of auction shall stand forfeited. Further un paid 15% amount towards security shall be recovered as arrears of land revenue and such bidder shall debarred from participation in any future auctions/Tenders/competitive bidding process in respect of any area for obtaining mineral concession in the State for a period of 5 years;
- 18. The lessee shall be liable to pay dead rent as determined through open auction or shall pay royalty in respect of each of the minor minerals extracted or removed or consumed by him or his agent, manager, employee

etc., whichever is more. The royalty shall be payable at the rates prescribed in First Schedule appended to the State Rules and as may be revised by the State Government from time to time.

- 19. The lessee shall also deposit/pay an additional amount equal to 10% of the due dead rent alongwith installments towards the 'Mines and Minerals Development, Restoration and Rehabilitation Fund';
- 20. The lessee shall be liable to pay advance Income Tax as per provisions of Section 206 (c) of the Income Tax Act, in addition to the dead rent payable as per term and condition of the lease deed;
- On enhancement of the annual dead rent with expiry of every three years period, the lessee shall deposit the balance amount of security so as to upscale the security amount equal to 25% of the revised annual dead rent as applicable for one year with respect to the next block of three years;
- 22. No interest, whatsoever, shall be payable on the security amount deposited under proper security head of the Government;
- 23. The LoI holder/lessee shall also furnish a solvent surety for a sum equal to the amount of the annual bid for execution of the lease deed. In case the surety offered by the lessee(s) during the subsistence of the lease is not found solvent, the lessee(s) shall offer another solvent surety and a supplementary deed to this effect shall be executed;
- 24. The mining lessee shall got prepare a Mining Plan along with the Mine Closure Plan (Progressive & Final) from the Recognised Qualified Person as per chapter 10 of the "Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012" for mining area granted on lease. The lessee shall not commence mining operations in any area except in accordance with such Mining Plan duly approved by an officer authorized by the Director, Mines & Geology, in this behalf.

Further, the actual mining will be allowed to be commenced only after prior Environmental Clearance is obtained by the LoI holder/lessee for the Mining lease area from Competent Authority as required under notification dated 14/09/2006 issued by the MoE&F, GoI or as amended from time to time.

- 25. The lessee would also be liable to pay following to the land owners;
 - (a) The annual rent in respect of the land area blocked under the concession but not being operated, and
 - (b) The rent plus compensation in respect of the area used for actual mining operations.

The amount of annual rent and the compensation shall be settled mutually between the landowner and the mining lessee. In case of non-settlement of the rent and compensation, the same shall be decided by the District Collector concerned in accordance with the provisions of Chapter 9 of the "Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, and Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012".

- 26. The total mineral excavated and stacked by the concession holder within the area granted on mining lease shall not exceed two times of the average monthly production as per approved Mining Plan at any point of time;
- 27. The Mining lessee shall not stock any mineral outside the concession area granted on mining lease, without obtaining a valid mineral dealer license as per provisions contained in Chapter 14 of the "Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012";
- 28. The lessee shall not carry out any mining operations in any reserved/protected forest or any area prohibited by any law in force in India, or prohibited by any authority without obtaining prior permission in writing from such authority or officer authorized in this behalf. In case of refusal of permission by such authority or officer authorized in this behalf, lessee(s) shall not be entitled to claim any relief in payment of dead rent on this account;
- 29. That no mining operation shall be allowed in the urbansizable zone of area notified by Town and Country Planning Department. Further, in case of the agriculture zone notified by Town and Country Planning Department mining shall be permissible only after obtaining prior permission from the competent authority;

- 30. A safety margin of two meters (2m) shall be maintained above the ground water table while undertaking mining and no mining operations shall be permissible below this level unless a specific permission is obtained from the competent authority in this behalf;
- 31. The lessee shall not undertake any mining operations in the area granted on mining lease without obtaining requisite permission from the competent authority as required for undertaking mining operations under relevant laws:
- 32. In case any lease holder intends to install stone crusher inside lease hold area, the same can be installed as per siting parameters of Environment Department
- 33. The lessee shall be under obligation to carryout mining in accordance with all other provisions applicable as per Mines Act, 1952, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, Forest (Conservation) Act, 1980 and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under Wild Life (Protection) Act, 1972, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981;
- 34. That in case of village Dariyapur and Garanpur Kalan, the area had been notified for grant of lease in relaxation of Rule 7(1) of the Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012 with special condition that:-
 - "Even if hard rock is found at any stage, explosive will not be allowed to be used and the area used in these three particular blocks shall be refilled with ordinary earth up to natural ground level after excavation of Gypsum mineral. In this way, even if concession holder had to bring additional soil from area outside lease hold area (soil other than overburden) he shall bring and undertake to refill the area up to original level/ adjoining level of land."
- 35. M/s Om Minerals, one of the contractors has filed a CWP No. 7991 of 2014. A few other LoI holders/contractors have also filed separate CWPs before the Hon'ble Punjab and Haryana High Court challenging the levy of Stamp Duty on execution of 'Lease deed'. The said matter is still pending for adjudication before Hon'ble Punjab and Haryana Court; accordingly, the charging of stamp duty for the execution of lease deed shall be as per outcome of the said CWP's;
- 36. Further information, if any required, can be had on any working day from the office of the Mining Officer, Mines & Geology Department, Hisar and Bhiwani or from the O/o the Director General, Mines and Geology, Haryana, 30 Bays Building, Sector-17, Chandigarh.

ARUN KUMAR GUPTA, Director General, Mines & Geology Department, Haryana.

Annexure-A

Guideline for Online Payments in e-Auction

Post registration, bidder shall proceed for bidding. Bidder shall proceed to select the e-auction he is interested in. On the respective Department's page in the e-auction portal, the Bidder would have following options to make payment for e-Service fee & EMD:

- a. Debit Card
- b. Net Banking
- c. RTGS/NEFT
- d. OTC

Operative Procedures for Bidder Payments

A) Debit Card

The procedure for paying through Debit Card will be as follows:

- (i) Bidder selects Debit Card option in e-Procurement portal.
- (ii) The e-Procurement portal displays the amount and the card charges to be paid by bidder. The portal also displays the total amount to be paid by the bidder.
- (iii) Bidder clicks on "Continue" button.
- (iv) The e-Procurement portal takes the bidder to Debit Card payment gateway screen.
- (v) Bidder enters card credentials and confirms payment.
- (vi) The gateway verifies the credentials and confirms with "successful" or "failure" message, which is confirmed back to e-Procurement portal.
- (vii) The page is automatically routed back to e-Procurement portal.
- (viii) The status of the payment is displayed as "successful" in e-Procurement portal.

 The e-Procurement portal also generates a receipt for all successful transactions. The bidder can take a print out of the same.
- (ix) The e-Procurement portal allows Bidder to process another payment attempt in case payments are not successful for previous attempt.
- B) Net banking.

The procedure for paying through Netbanking will be as follows:

- (i) Bidder selects Netbanking option in e-Procurement portal.
- (ii) The e-Procurement portal displays the amount to be paid by bidder.
- (iii) Bidder clicks on "Continue" button.
- (iv) The e-Procurement portal takes the bidder to Netbanking payment gateway screen displaying list of Banks.
- (v) Bidder chooses his / her Bank.
- (vi) The Netbanking gateway redirects Bidder to the Netbanking page of the selected Bank.
- (vii) Bidder enters his account credentials and confirms payment.
- (viii) The Bank verifies the credentials and confirms with "successful" or "failure" message to the Netbanking gateway which is confirmed back to e-Procurement portal.
- (ix) The page is automatically routed back to e-Procurement portal.
- (x) The status of the payment is displayed as "successful" in e-Procurement portal.

 The e-Procurement portal also generates a receipt for all successful transactions. The bidder can take a print out of the same.
- (xi) The e-Procurement portal allows Bidder to process another payment attempt in case payments are not successful for previous attempt.

(C) RTGS/ NEFT

The bidder shall have the option to make the EMD payment via RTGS/ NEFT. Using this module, bidder would be able to pay from their existing Bank account through RTGS/NEFT. This would offer a wide reach for more than 90,000 bank branches and would enable the bidder to make the payment from almost any bank branch across India.

- i. Bidder shall log into the client e-procurement portal using user id and password as per existing process and selects the RTGS/NEFT payment option.
- ii. Upon doing so, the e-procurement portal shall generate a pre-filled challan. The challan will have all the details that is required by the bidder to make RTGS-NEFT payment.
- iii. Each challan shall therefore include the following details that will be pre-populated:

Beneficiary account no: (unique alphanumeric code for e-tendering) Beneficiary

IFSC Code:

Amount:

Beneficiary bank branch:

Beneficiary name:

- iv. The Bidder shall be required to take a print of this challan and make the RTGS/NEFT on the basis of the details printed on the challan.
- v. The bidder would remit the funds latest by **30.05.2016** in advance and make the payment via OTC to the beneficiary account number as mentioned in the challan.
- vi. Post making the payment, the bidder would login to the e-Auction portal and go to the payment page. On clicking the RTGS / NEFT mode of payment, there would be a link for real time validation. On clicking the same, system would do auto validation of the payment made.

List of Net banking banks

- 1. Allahabad Bank
- 2. Axis Bank
- 3. Bank of Bahrain and Kuwait
- 4. Bank of Baroda
- 5. Bank of India
- 6. Bank of Maharashtra
- 7. Canara Bank
- 8. City Union Bank
- 9. Central Bank of India
- 10. Catholic Syrian Bank
- 11. Corporation Bank
- 12. Deutsche Bank
- 13. Development Credit Bank
- 14. Dhanlaxmi Bank
- 15. Federal Bank
- 16. HDFC Bank
- 17. ICICI Bank
- 18. IDBI Bank
- 19. Indian Bank
- 20. Indian Overseas Bank
- 21. Indusind Bank
- 22. ING Vysya Bank
- 23. J & K Bank
- 24. Karnataka Bank
- 25. Kotak Mahindra Bank
- 26. Karur Vysys Bank
- 27. Punjab National Bank
- 28. Oriental Bank of Commerce
- 29. South Indian Bank

- 30. Standard Chartered Bank
- 31. State Bank Of Bikaner and Jaipur
- 32. State Bank of Hyderabad
- 33. State Bank of India
- 34. State Bank of Mysore
- 35. State Bank of Travencore
- 36. State Bank Of Patiala
- 37. Tamilnad Mercantile Bank
- 38. Union Bank of India
- 39. United Bank of India
- 40. Vijaya Bank
- 41. Yes Bank

(D) OTC

The bidder shall have the option to make the EMD payment via OTC. Using this module, bidder would be able to pay from their existing ICICI Bank account through CASH/DD/ICICI BANK CHEQUE.

- i. Bidder shall log into the client e-procurement portal using user id and password as per existing process and selects the OTC payment option.
- ii. Upon doing so, the e-procurement portal shall generate a pre-filled challan. The challan will have all the details that is required by the bidder to make OTC payment.
- iii. Each challan shall therefore include the following details that will be pre-populated:

Beneficiary account no: (unique alphanumeric code for e-tendering) Beneficiary IFSC Code:

Amount:

Beneficiary bank branch:

Beneficiary name:

- iv. The Bidder shall be required to take a print of this challan and make the OTC on the basis of the details printed on the challan.
- v. The bidder would remit the funds latest by **30.05.2016** in advance and make the payment via OTC to the beneficiary account number as mentioned in the challan.

For making payment through Demand Draft against the online Challan generated for OTC:

If the amount is more than 50,000 (Fifty Thousand) then the intended bidders are required to provide ICICI Bank cheque or draw demand draft in favour of below furnished details:-

Sr No.	Account Name/ title	Account No.
1	GOH E- PROC EMD ESCROW A/C DSND - MINGEO	001305010048

<u>Instructions for Intending Bidders to participate in Auction</u>

How to Participate:

Part A

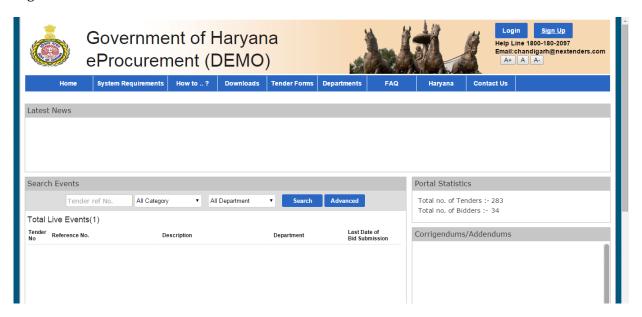
E-Auction Portal Signup & Bidding Process

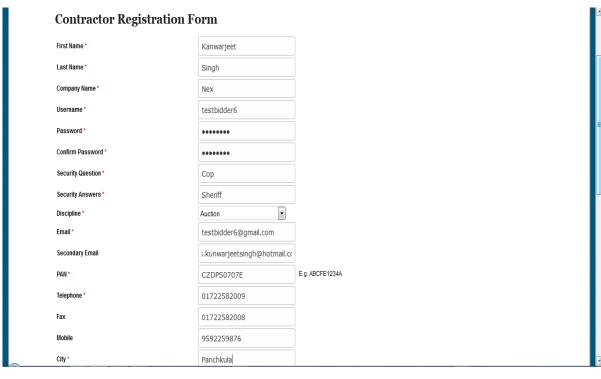
Web portal for e-Auction of Haryana Single e-Procurement portal at https://haryanaeprocurement.gov.in

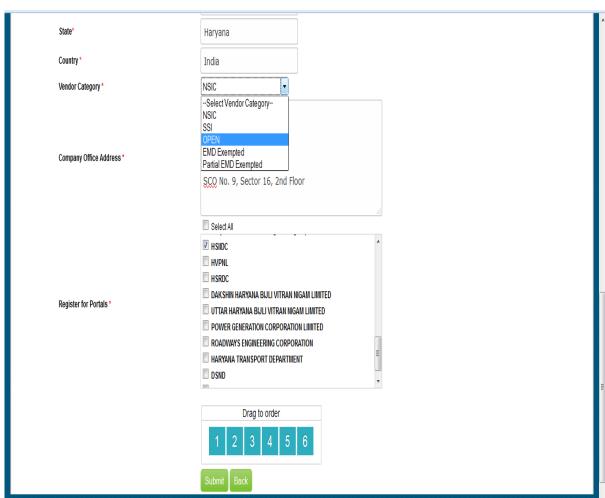
1. Signup: Bidder must required to create a login ID and password on the e-Procurement Portal by providing the basic information. Signup on the portal is free. Bidder has to create the login account for participating online into e- auction.

After filling up all the required details carefully, bidder has to click on submit button in order to complete the Sign-up process.

On completion of the Sign-up process, bidder will receive a registration activation mail on the registered email ID.



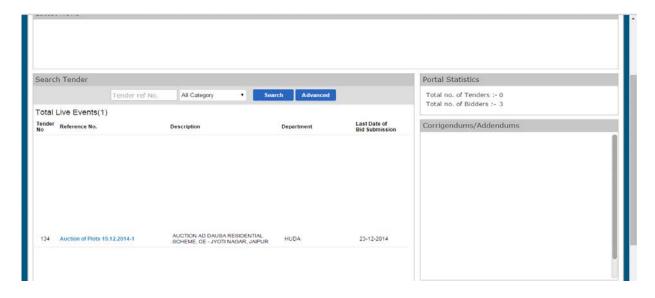






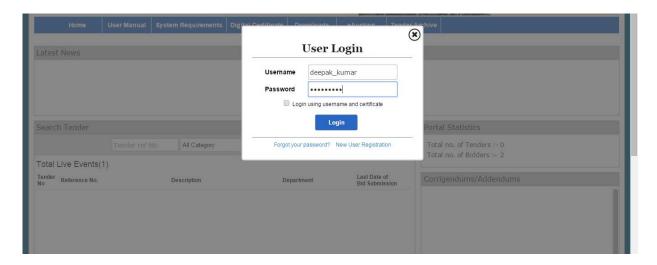
Note: (a) In case of Individual the bidder must entre his/her name or mentione Individual against company Name.

- (b) For vendor Category select 'OPEN' from the drop-down.
- 2. <u>Search Auction</u>: Bidder can view the live auction events and download the related documents without login to the portal.



3. <u>Bidder Login:</u> Login to the eAuction portal for online participation on Auction event.Interested bidders have to enter their online registered login ID and password with the portal. If the bidder forgets his/her password, the same can be retrieved by clicking on the "forget your password" link at the website,

and thereby furnish their registered security question and answer to recover password at the e-Auction website. After receiving the correct security question and answer, bidder will receive auto-generated email from the system containing the password reset link.

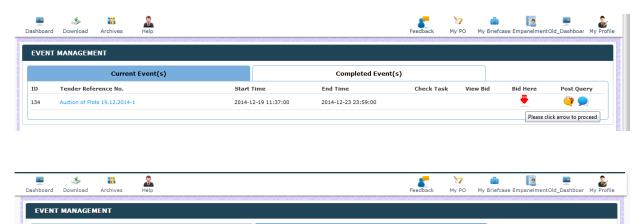


- 4. <u>Dashboard</u>: After successful login, bidder will be redirected to the dashboard. Dashboard is divided into 2 Sections.
 - <u>a.</u> <u>Current Events:</u> Current events will display the live auctions. Bidder can be able to participate in any of the live auction as per the scheduled date and time.
 - **b.** Completed Events: Once the auction will be concluded, it will shown in this section Current event tab. Bidder can check for the reports in this section after the auction will be concluded.

Bidder has to click on "Bid Here" link in order to bid on the auction he/she wish to participate.

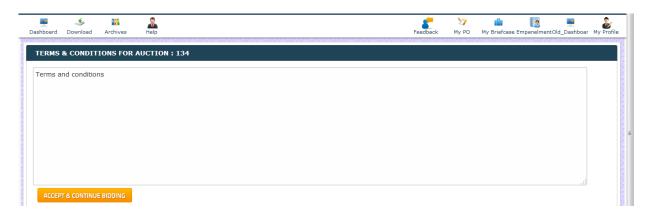
Tender Reference No

Record not found.



End Time

5. <u>Acceptance of terms and conditions:</u> Bidder has to read carefully & accept the auction terms and conditions before bidding online on the e-Auction portal. And the bidder will be redirected to the e-Payment page.



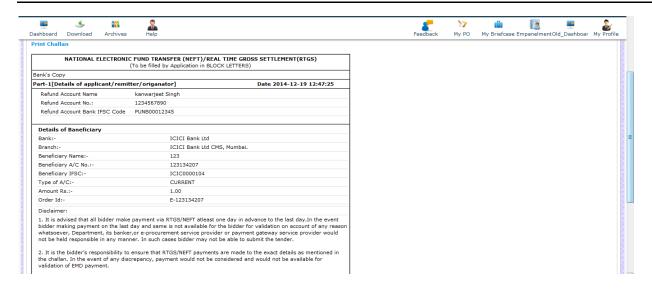
6. Online payment for eService and EMD/ Registration fee: Bidder is mandatorily required to pay eService fee of Rs. 1000/- using the online payment gateway through their Debit Card/Internet Banking.

For EMD/Registration fee payment bidders can have the option to make online payment of the amount through Debit Card/Internet Banking/RTGS/NEFT/OTC.

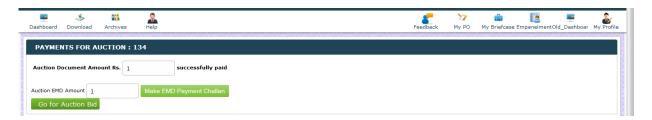
To make payment through RTGS/NEFT/OTC a pre-filled Challan shall be generated at the e-Auction portal for EMD/Registration fee payment. And remit the funds at least T+1 working day in advance to the closing date of e-Bidding.

So therefore all the intending bidders are require submitting of their EMD / Registration fee amount well in advance keeping in view the closing date & time of the e-Auction event / Online Registration.

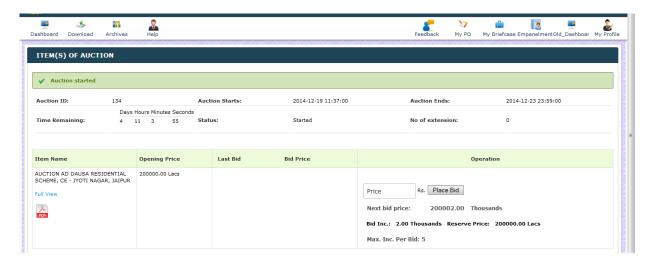




Auction Bidding: Once the e- challan generated by respective bidder is verified by the system, he/she can enter into the online auction hall by clicking on the button "Go for Auction Bid".



On the bidding page, bidder is required to bid on the auction. Bidder can check for the Auction Documents/attachments in the real time. Page can also have a view to see the time remaining in the auction bidding.



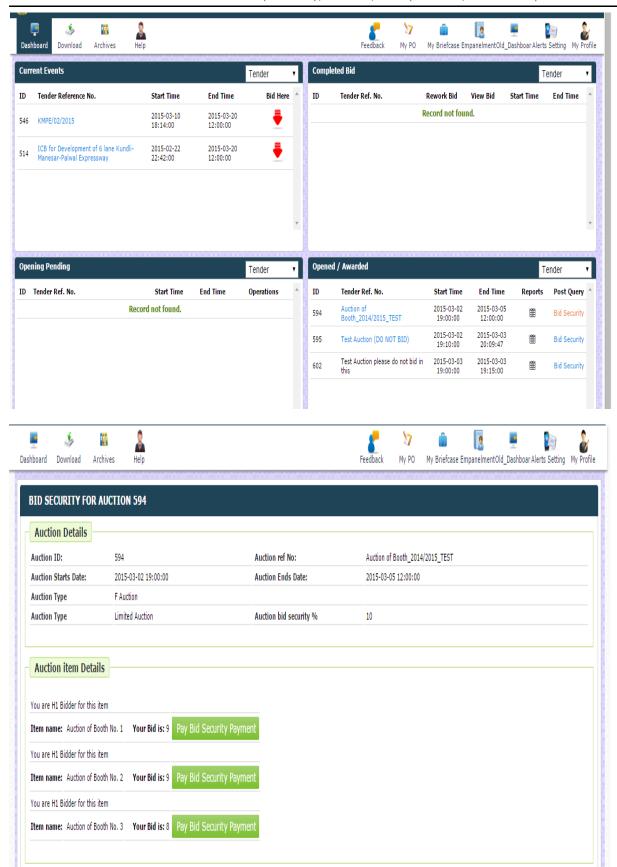
Part B

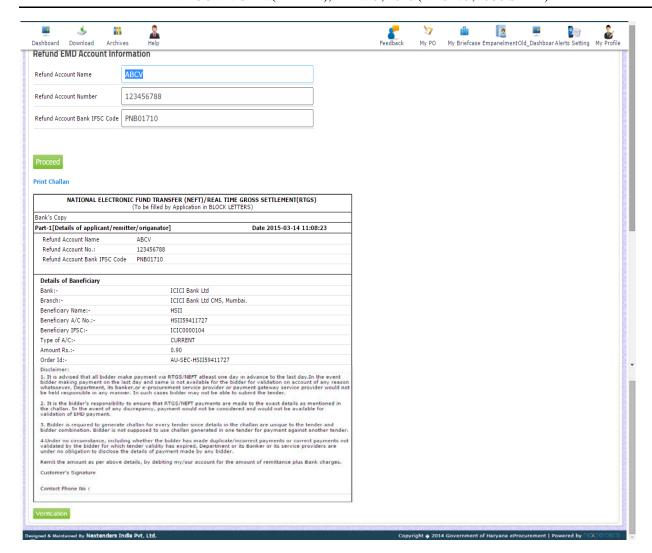
Closing

The auction remains live till the closing date and time as defined in the bid document. Bidders can see the closing date and time by accessing the auction document and even on the e-Auction portal. However, the time of e-Auction will automatically be extended if the bidder tries to bid in the last 10 minutes before the closing time of the auction for the next 10 minutes. However, the increment during extended period will be multiple of 100000 (one lakh) instead of 50,000 (fifty thousand).

E-Payment for Bid Security Amount by the H1 Bidder:

The highest bidder has to initiate online payment towards 'Bid Security' under the stipulated time frame as referred to the event Document. The concern bidder require to follow the below given screenshot for making payment online through RTGS/NEFT/OTC to the beneficiary account number pre-filled generated under the e-challan. The aforesaid bidder must remit the fund in due course of time.





Note- A training-cum-orientation program for the intending bidders will be held on 14th, 21st and 28th May, 2016 at Panchkula office of Nextenders, C/o Director, Supplies and Disposal Department, Haryana, SCO No. 9, 2nd Floor, Sector-16, Panchkula from 11:00 A.M. to 12:00 Noon Parties interested in attending the same are requested to contact/confirm participation to Sh. Kanwarjeet Singh Mobile 09592259876, Sh. Sat Dev Sharma 9872252144 or the helpdesk on Toll Free No. 1800-180-2097 and 0172-2582008/2582009/2618292 or through E-mail: chandigarh@nextenders.com.

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर 17, पंचकूला

अधिसूचना

दिनांकः २९ अप्रैल, २०१६

क्रमांक:रा0नि0आ0/3ई—II/2016/3862.— हरियाणा पंचायती राज अधिनियम,1994 की धारा 161 की उप—धारा (4) का अनुसरण करते हुये, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त, एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम जो जिला परिषद के प्रधान और उप—प्रधान निर्वाचित हुये हैं, अधिसूचित किए जाते हैं:—

जिला परिषद	नाम	पिता / पति का नाम	पद का नाम
	श्री / श्रीमती / कुमारी	श्री	
महेन्द्रगढ़	राजेश	संजीव	प्रधान
	सुशीला	धर्मदेव	उप–प्रधान

पंचकूलाः दिनांक २९ अप्रैल, २०१६. राजीव शर्मा, राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA NIRVACHAN SADAN, PLOT NO.02, SECTOR 17, PANCHKULA

Notification

The 29th April, 2016

No.SEC/3E-II/2016/3862.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of Section 161 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, the State Election Commissioner, Haryana hereby notifies the names of the following persons, who have been elected as President and Vice-President of Zila Parishads:-

Zila Parishad	Name	Father's/Husband's Name Sh.	Name of Office
	Sh./Smt./Kumari		
Mahendergarh	Rajesh	Sanjeev	President
	Sushila	Dharm Dev	Vice-President

Panchkula: The 29th April, 2016. RAJEEV SHARMA, State Election Commissioner, Haryana.

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर 17, पंचकूला

अधिसूचना

दिनांकः 29 अप्रैल, 2016

क्रमांकः रा0नि0आ0 / 3ई— | | / 2016 / 3870.— हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 161 की उप—धारा (4) का अनुसरण करते हुये, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त, एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम जो निम्नलिखित पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित हुये हैं, अधिसूचित किए जाते हैं:—

जिला का नाम	खण्ड / पंचायत समिति	नाम सर्व /	पिता / पति का नाम	पद का नाम
	का नाम	श्री / श्रीमती		
अंबाला	साहा	मोहित	सुरिन्द्र कुमार	अध्यक्ष
		संगीता रानी	अमित कुमार	उपाध्यक्ष
	अम्बाला – ॥	जगप्रीत कौर	जसविन्द्र सिंह	अध्यक्ष
		महिन्द्र कौर	गज्जन सिंह	उपाध्यक्ष

सिरसा	बड़ागुढा	गुरविन्द्र सिंह	जगसीर सिंह	अध्यक्ष
		बलकौर सिंह	मग्घर सिंह	उपाध्यक्ष
	डबवाली	सुरेन्द्र	बलबहादर	अध्यक्ष
		अमृतपाल सिंह	दर्शन सिंह	उपाध्यक्ष
	ऐलनाबाद	कुलदीप कौर	पूर्ण सिंह	अध्यक्ष
		गणेशा राम	अमीलाल	उपाध्यक्ष
	नाथुसरी चौपटा	विरेन्द्र कुमार	गोपीराम	अध्यक्ष
		विनोद कुमार	रामस्वरूप	उपाध्यक्ष
	औढां	मनोज कुमार	सुरेन्द्र कुमार	अध्यक्ष
		बलकार सिंह	जगराज सिंह	उपाध्यक्ष
	सिरसा	ममता रानी	राजकुमार	अध्यक्ष
		मंगत लाल	राजकुमार	उपाध्यक्ष
रोहतक	महम	सुमित्रा	समुन्द्र	अध्यक्ष
		वरूण	श्रीकृष्ण	उपाध्यक्ष

पंचकूलाः दिनांक 29 अप्रैल, 2016. राजीव शर्मा, राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

STATE ELECTION COMMISSION, HARYANA NIRVACHAN SADAN, PLOT NO.02, SECTOR 17, PANCHKULA

Notification

The 29th April, 2016

No.SEC/3E-II/2016/3870.—In pursuance of the provisions of Sub-section (4) of Section 161 of the Haryana Panchayati Raj Act, 1994, the State Election Commissioner, Haryana hereby notifies the names of the following persons, who have been elected as Chairman and Vice-Chairman of the following Panchayat Samitis:-

District	Panchayat Samiti	Name	Father's/Husband's Name	Name of Office
		Sh./Smt./Kumari	Sh.	
Ambala	Saha	Mohit	Surinder Kumar	Chairman
		Sangeeta Rani	Amit Kumar	Vice-Chairman
	Ambala – II	Jagpreet Kaur	Jasvinder Singh	Chairman
		Mohinder Kaur	Gajjan Singh	Vice- Chairman
Sirsa	Baragudha	Gurvinder Singh	Jagseer Singh	Chairman
		Balkor Singh	Maghar Singh	Vice-Chairman
	Dabwali	Surender	Balbhadar	Chairman
		Amrit Pal Singh	Darshan Singh	Vice- Chairman
	Ellenabad	Kuldeep Kaur	Puran Singh	Chairman
		Ganesha Ram	Ami Lal	Vice-Chairman
	Nathusari Chopta	Vriender Kumar	Gopi Ram	Chairman
		Vinod Kumar	Ramsavroop	Vice-Chairman
	Odhan	Manoj Kumar	Surender Kumar	Chairman
		Balkar Singh	Jagraj Singh	Vice-Chairman
	Sirsa	Mamta Rani	Raj Kumar	Chairman
		Mangat Lal	Raj Kumar	Vice- Chairman
Rohtak	Meham	Sumitra	Samunder	Chairman
		Varun	Shri Krishan	Vice-Chairman

Panchkula: The 29th April, 2016. RAJEEV SHARMA, State Election Commissioner, Haryana.

हरियाणा सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 अप्रैल, 2016

संख्या 13/1/2016-6T(I).— हिरयाणा मोटर यान कराधान अधिनियम, 2013 (2013 का 28), की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हिरयाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हिरयाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 13/15/2010-6परि0(I), दिनांक 5 जून, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं; अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग, अधिसूचना संख्या 13/15/2010—6परि0(I), दिनांक 5 जून, 2015 में, तालिका में ''विशेष प्रयोजनों के लिए वाहन'' शीर्ष के नीचे,—

- (i) खाना 2 के नीचे, क्रम संख्या 3 तथा 4 के सामने, "एम्बुलेंस" चिहन तथा शब्द का लोप कर दिया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 4 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :--

1	2	3
5.	राज्य / केन्द्रीय सरकार के विभागों, राज्य / केन्द्रीय सरकार के बोर्डों / निगमों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा रेड क्रॉस सोसाईटी अथवा आयकर अधिनियम के अधीन पंजीकृत ऐसी कोई धर्मार्थ संस्था के स्वामित्वाधीन एम्बुलेंस, जो ऐसे वाहनों के इस्तेमाल के लिए शून्य / नाममात्र फीस लेते हों	वाहन के मूल्य का 1%
6.	क्रम संख्या 5 पर वर्णित विभागों / कानूनी निकायों के स्वामित्वाधीन से भिन्न एम्बुलेंस तथा ऐसे वाहनों के उपयोग के लिए शून्य / नाममात्र फीस प्रभारित करने वाले।	वाहन के मूल्य का 2%
7.	"लाभ अर्जित" करने वाले अस्पताल/क्लीनिक/ नर्सिंग होम से सम्बन्धित एम्बुलेंस।	वाहन के मूल्य का 6%

- (iii) टिप्पण में, पैरा 8 के बाद, निम्नलिखित पैरा जोड़ दिया जाएगा, अर्थात्:--
 - "9. तालिका में क्रम संख्या 5 तथा 6 पर वर्णित ''एम्बुलेंस'' अभिघात रोगियों (ट्रामा) को निःशुल्क परिवहन करेगी।''।

एस० एस० ढिल्लों, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Notification

The 29th April, 2016

No.13/1/2016-6T(I).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Haryana Motor Vehicles Taxation Act, 2013 (28 of 2013), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Transport Department, Notification No. 13/15/2010-6T(I), dated the 5th June, 2015, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Transport Department, Notification No. 13/15/2010-6T(I), dated the 5th June, 2015, in the Table, under heading "VEHICLE FOR SPECIAL PURPOSE",-

- (i) under column 2, against serial number 3 and 4, the sign and word "ambulance" shall be omitted;
- (ii) after serial number 4, the following serial numbers and entries against there shall be inserted, namely:-

1	2	3
5.	Ambulances owned by State/Central Government Departments, Board/Corporations/Public Sector Undertakings of State/Central Government or by Red Cross Society or any such Charitable Body registered as such under the Income Tax Act charging nil/nominal fees for use of such vehicles	1% of the value of vehicle
6.	Ambulances other than those owned by Departments/Statutory Bodies mentioned at Sr. No. 5 and charging nil/nominal fees for the use of such vehicles	2% of the value of vehicle
7.	Ambulance belonging to Hospitals/Clinics/Nursing Homes 'earning profit'	6% of the value of vehicle

- (iii) in the Note, after para 8, the following para shall be added, namely:-
 - "9. The "ambulances" mentioned at serial number 5 and 6 of the Table shall transport Trauma patients free of cost.".

S. S. DHILLON, Additional Chief Secretary to Government Haryana, Transport Department.

54283—C.S.—H.G.P., Chd.